SHRIMATI S. G. INDIRA: As far as diversion of forest land for non-forestry use is concerned—as given in the statement—in respect of Tamil Nadu, 66 proposals were approved. Out of 66 approved proposals, 4 have been rejected. I would like to know from the hon. Minister, what are the reasons for rejecting the four proposals?

SHRI T.R. BAALU: Sir, since those proposals were not according to the Forest (Conservation) Act and also the Wildlife Act, that is why they have been rejected.

Indian students in foreign universities

*349. SHRI R. P. GOENKA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether any study has been conducted to analyse the problems increasingly faced by the larger number of Indian students enrolling themselves in foreign universities for higher education and specialised courses; and

(b) if so, the details thereof and the action taken/proposed to be taken to safeguard the interests of the student community, especially measures against bogus foreign universities?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR.MURLI MANOHAR JOSHI): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

While no specific study on the problems of Indian students studying in foreign universities has been conducted by the Government according to the information compiled by the Association of Indian Universities on the basis of advertisements appearing in the Indian newspapers 144 foreign universities/colleges/institutions are offering various courses of study to the Indian students. With a view to safeguard the interests of the student community, the University Grants Commission has framed draft Regulations for regulating the entry into and operations of foreign universities/educational institutions in the country. Besides, the Government has constituted a Committee with the objective of regulating operations of foreign educational institutions in India. The Government

has also taken up the matter with Indian Missions in major foreign countries, such as United States of America.Canada, United Kingdom, Australia and New Zealand, to check on the antecedents and credibility of educational institutions from these countries offering education to Indian students.

श्री आर.पी.गोयनका : सभापति महोदय, मेरा सवाल और सप्लीमेंटरी सिर्फ एक ही है कि कुछ दिन पहले मंत्री जी ने कहा था कि 'law against bogus foreign universities soon'. इस बात को दो महीने हो गए है। तो मंत्री जी कब तक इस किस्म का एक्ट ला रहे है या कुछ एक्शन ले रहे है।

डा. मुरली मनोहर जोशी : श्रीमन्, इस विषय में हमारे विभाग और यू.जी.सी. दोनो ने कुछ कार्यवाहिंया की है। एक तो इस संबंध में हमारे विभाग ने 19 सदस्यों की एक समिति बनाई है जो इस व्यापक प्रश्न पर पूरा विचार कर के रिपोर्ट देने वाली है। दूसरा, यू.जी.सी. ने इस संबंध में कुछ सुझाव बनाए हैं क्योंकि इस में बहुत से मामले ऐसे हैं जिन पर राज्य सरकारों से भी परामर्श करना पड़ रहा है। इन कानूनों का क्रियान्वयन करने में राज्य सरकारों की सहायता की भी जरूरत पड़ती है। इस दृष्टि से एक व्यापक कानून तैयार हो रहा है और विधि विभाग के साथ उस पर परामर्श करने के पश्चात हम उसे कैबिनेट की मंजूरी के बाद आप के समक्ष प्रस्तुत कर देगे। लेकिन मैं आप को बता दूंगा कि इस बारे में सरकार पूरी तौर पर प्रयत्नशील है और इन बोगस विश्वविधालयों के बारे में हम ने अपने हाई-कमिश्नर्स और राजदूतों से भी जानकारिंया प्राप्त की है। उस की भी पूरी छानबीन की है। उस को ध्यान में रखते हुए ताकि हमारे विघार्थियों का कोई अहित न हो, हम शीघ्र ही एक कानून बनाने जा रहे हैं ।

श्रीमती चन्द्रकला पांडेः धन्यवाद, सभापति महोदय। महोदय, अभी हमारे यहां यू.एस.एस. से पास कुछ डाक्टर्स आंदोलन कर रहे थे जिन को मिनिस्ट्री ने कहा कि उन को एक टेस्ट देना होगा।मैं मंत्री महोदय से पुछना चाहूंगी कि आप जल्द से जल्द उस टेस्ट के लिए कोई कार्यवाही कर रहे है। दूसरे, फॉरेन यूनिवर्सिटीज के जो आकर्षक विज्ञापन निकालते है जिस से दिग्भ्रिमित होकर बहुत से छात्र उन में भर्ती हो जाते हैं, क्या आप ऐसे निर्देश देंगे कि आप के मंत्रालय से पूछे बिना ऐसे विज्ञापन न निकाले जा सकें।

डा. मुरली मनोहर जोशी : सभापति जी, जहां तक डाक्टर्स का सवाल है, वह स्वास्थय मंत्रालय के द्वारा नियमित होते हैं और जहां तक मेरी जानकारी है, उन की जो मेडिकल ऐसोसिएशन है, उस ने यह निर्देश जारी किए हैं और मै आप का सुझाव जल्द से जल्द माननीय स्वास्थ्य मंत्री और उस संस्था तक पहूंचा दूंगा। यह काम हमारा मंत्रालय नहीं करता है। अब जहां तक आपका दूसरा प्रश्न है, हम ने बार-बार इस संबंध में प्रयास किया है कि उन विश्वविघालयों की छानबीन करें

जो कि इस देश के लिए अनुपयुक्त है अथवा जो एक प्रकार से अवैध विश्वविधालय है। इस संबंध में जितनी जानकारी मिलती है, उस की हम सूची भी देते हैं, लेकिन आने वाले समय में उन विश्वविधालय में प्रवेश कैसे हो, जो कानून हम बनाना चाहते है, उस के द्वारा नियमित करेंगे क्योंकि अब जिस प्रकार के डबल्यू.टी.ओ. के प्रावधान है, उनको देखते हुए आने वाले समय में शिक्षा एक सेवा के रूप में खुलने की परिस्थिति पैदा हो सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम एक टयापक कानून बना रहे है। और शीघ्र ही वह कानून आप के अनुमोदन के लिए यहां प्रस्तुत किया जाएगा।

SHRI EDUARDO FALEIRO: Sir, foreign educational institutions are taking over the educational market of India at all levels, not just at the university level, but even at the primary and high school levels. Sir this runs counter to the National Educational Policy of 1986.1 would like to know from the hon. Minister whether the Government is contemplating a review of the National Educational Policy, And, have you made any commitments, regarding this subject, at the GATT negotiations?

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Sir, as far as the question of encroachment on Indian education market by foreign universities and educational institutions is concerned, I would like to assure the hon. Member that the Government of India is aware of the magnitude of the problem, and when the Educational Bill, as contemplated by the Constitution (Amendment) Bill, will come into force, many of these problems will be solved. We will cover all those things under that Bill. And as regards higher education, I would like to say that the UGC is on the job. As I have already said, an amendment to that aspect is under consideration of the Government, and will be placed before the House very soon.

*350. *[The questioner (Shri Parmeshwar Kumar Agarwalla) was absent for answer vide pages* 35-36]

Disaster Management System in Railways

*351. SHRI MOOLCHAND MEENA:
DR.T. SUBBARAMI REDDY:†

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether in the wake of criticism of rescue and relief operations

†The question was actually asked on the floor of the House by Dr. T. Subbarami Reddy.